

LM-107

Judicial Process

Master of Law LL.M -12/16/17

Second year, Examination-2019

Time: 3 Hours

Max. Marks: 80

Note:- This paper is of **Eighty (80)** marks divided into **three (03)** Section A, B and C. Attempt the question contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

यह प्रश्न-पत्र अस्सी (80) अंकों का है जो तीन (03) खण्डों क, ख तथा ग में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है।

Section-A [k. M&d½

(Long Answer Type Question) ¼[k. M&d½

Note:- Section 'A' contains four (04) long-answer-type questions of Nineteen (19) marks each. Learners are required to answer any two (02) questions only.

(2×19=38)

खण्ड 'क' में चार (04) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए उन्नीस (19) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Describe the analytical and evaluative working of the judicial process in the area of personal liberty under the Indian constitution.

भारतीय संविधान के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्षेत्र में न्यायिक प्रक्रिया की कार्यप्रणाली का विश्लेषणात्मक एवं मूल्यांकनात्मक वर्णन कीजिए।

2. Object of precedent is create fairness and provide certainty in Law. Whether the doctrine judicial precedent hamper the judicial creativity? If yes, to what extent? Critically discuss.

न्यायिक पूर्व-निर्णय का उद्देश्य विधि में ऋणुता तथा निश्चितता प्रदान करना है। क्या न्यायिक पूर्व-निर्णय का सिद्धान्त, न्यायिक सृजनता में रुकावट उत्पन्न करता है? यदि हाँ तो किस सीमा तक? समालोचनात्मक विवेचन कीजिए।

3. 'Law is an instrument of social change'. Discuss in the light of Roscoe pound's view on the subject.

'विधि सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। इस विषय पर रॉस्को पाउण्ड के विचारों के आलोक में विवेचन कीजिए।

4. The extent of freedom of speech and expression in a country is a test to determine how much that country is democratic". Explain the expanding scope of freedom of speech and expression with relevant judicial decisions.

“किसी देश में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा से यह परख होती है कि वह देश कितना लोकतांत्रिक है” भारत में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बढ़ते दायरे का उपर्युक्त न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए।

Section-B ¼[k. M& [k½

(Short Answer Type Question) @¼y?kq mÜkj ka okys i t u½

Note:- Section ‘B’ contains eight (08) short answer type questions of Eight (08) marks each. Learners are required to answer any four (04) questions only.

(4×8=32)

uk½/%& खण्ड ‘ख’ में आठ (08) लघु उत्तरों वाले प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आठ (08) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. What do you understand by ‘Judicial reasoning’? Explain with examples.

न्यायिक हेतुवाद से आप क्या समझते हैं। उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए।

2. What do you understand by independence of judiciary? Critically examine the decision of Supreme Court of India in regard to National Judicial Appointment of Commission (NJAC).

स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) के सम्बंध में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

3. Write a note on 'Public Interest Litigation'.

'लोकहित वाद' पर एक टिप्पणी लिखिए।

4. 'Long delay in delivery of justice violates rule of Law'. Explain.

"विचारण में अत्यधिक विलम्ब विधि के शासन का उल्लंघन है।" स्पष्ट कीजिए।

5. Write a note on composition, Jurisdiction and powers of Lok Adalat.

लोक अदालत के गठन, अधिकारिता एवं शक्तियों पर एक लेख लिखिए।

6. Judicial process is an instrument of social change. Discuss.

"न्यायिक प्रक्रिया सामाजिक व्यवस्था का एक औजार है"। व्याख्या कीजिए।

7. Explain the concept of 'distributive Justice' and 'Corrective Justice'.

'वितरणात्मक न्याय' एवं 'सुधारात्मक न्याय' की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।

8. What do you understand by 'Judicial Activism'? Explain with the help of relevant case laws decided by supreme court of India.

'न्यायिक सक्रियता' से आप क्या समझते हैं? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्णित सम्बन्धित वादों की सहायता से व्याख्या कीजिए।

Section-C $\frac{1}{2}$ [k.M&x $\frac{1}{2}$

(Objective Type Questions) / (0Lr(u" B i z u)

Note:- Section 'C' contains ten (10) objective type questions of One (01) marks each. All the questions of this section are compulsory.

(10×1=10)

नोट:- खण्ड 'ग' में दस (10) वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक (01) अंक निर्धारित हैं। इस खण्ड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Indicate whether the following are True or False :

इंगित कीजिए कि निम्नलिखित सत्य है या असत्य :

1. Supreme Court is a court of reward under Article 125 of the constitution of India.

(True / False)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है।

(सत्य / असत्य)

2. Law declared by Supreme Court is binding on all courts including Supreme Court. (True/False)

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित सभी विधि सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं।

(सत्य / असत्य)

3. The High Courts in India are empowered to issue writs for the enforcement of fundamental rights only and not for other purpose. (True/False)

भारत में उच्च न्यायालयों को केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु और किसी अन्य कार्य हेतु नहीं, रिट जारी करने की शक्ति है

(सत्य / असत्य)

4. Judicial system and judicial process change with the change in society. (True/False)

न्याय-व्यवस्था एवं न्यायिक प्रक्रिया भी सामाजिक बदलाव के साथ बदलती है।

(सत्य / असत्य)

5. Section 115 of civil procedure code provides for 'revision'. (True/False)

दीवानी प्रक्रिया संहिता का धारा 115 पुनरीक्षण के लिए उपबन्धित है। (सत्य/असत्य)

6. The Family Courts are established is hear the cases relating to matrimonial disputes only.

(True/False)

पारिवारिक न्यायालयों का गठन केवल वैवाहिक विवादों को सुनने के लिए ही किया गया है।

(सत्य/असत्य)

7. The propounder of utilitarian theory of justice is Austin. (True/False)

न्याय के उपयोगितावादी सिद्धान्त के प्रवर्तक आस्टिन हैं। (सत्य/असत्य)

8. Like life, law is static. (True/False)

जीवन की तरह विधि भी स्थिर है। (सत्य/असत्य)

9. Article 38 of constitution of India provides for social justice. (True/False)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 'सामाजिक न्याय' को उपबन्धित करता है। (सत्य/असत्य)

10. "Preamble is a part of the constitution" is the pronouncement of the Supreme Court in Keshvanand Bharti case. (True/False)

"प्रस्तावना संविधान का एक अंग है"। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानन्द भारती के बाद में अभिनिर्धारित किया गया। (सत्य/असत्य)
